



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2214]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 9, 2019/आषाढ़ 18, 1941

No. 2214]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 9, 2019/ASHADHA 18, 1941

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2019

का.आ. 2439(अ).—केन्द्रीय सरकारकायह समाधान है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि खाद्य सामग्री में लगे उद्योग की सेवाएं जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की मद 6 के अधीन समाविष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा होंगी,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (d) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक खाद्य सामग्री में लगे उक्त उद्योग लोक उपयोगिता सेवाओं को सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/5/91-आईआर(पीएल)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2019

S.O. 2439(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services of the industry engaged in Food Stuffs, which is covered under item 6 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a Public Utility Service for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), the Central Government hereby declares the services of the said industry engaged in Food Stuffs to be a Public Utility Service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the date of publication of the notification.

[F. No. S-11017/5/91-IR (PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.